श्री मूलचन्द मीणा : सर, मैंने यह पूछा था कि आपने कौन-कौन से आर्थिक उपाय किए हैं, यह मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है ।

SHRI HIPHEI : The policy of the Government is good but its implementation seems to be very unsatisfactory. It is because the important posts, whether in the Union Government or in the State Governments, are manned by those who do not correctly understand the problems of the SC/ST community. I want to know whether the Government intends to post those Scheduled Caste and Scheduled Tribe IAS or IPS officers in those positions so that the problems are solved.

SHRI K. V. THANGKA BALU : Sir, there is a clear-cut direction to the State Governments particularly with regard to those areas where atrocities on the SC/ST people are there, to appoint Collectors / Commissioners and SPs and even Tehsil-level officers belonging to SC/ST and this has now been taken up from 1990 onwards to see that the atrocities-prone areas are looked after. There is now a tangible improvement in those areas and we hope that this problem will not occur in future.

SHRI HIPHEI : Union Government has issued instructions to the State Governments. But what about the Union Ministry itself?

SHRI K. V. THANGKA BALU : It is actually the State Government which has to take appropriate steps and we have asked them to implement it.

MR. CHAIRMAN : Next question.

पशुओं को लगने वाले टीके के मूल्य की वसूली

*464. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र पवर्तित योजना के अंतर्गत पशुओं को लगने वाली "मखरी" नामक बीमारी के नियंत्रण हेतु पशुओं को लगने वाले टीके के मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि पशु-पालकों से ली जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाज के कमजोर वर्ग के पशुपालक इस राशि को न दे सकने के कारण अपने पशुओं को टीका न लगवा कर उनसे हाथ धो बैठते हैं;

(ग) क्या सरकार पशुपालकों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के हिस्से के अतिरिक्त इसकी बीस प्रतिशत लागत को स्वयं वहन करेगी ताकि पशुपालकों को उक्त राशि का केवल 25 प्रतिशत ही देना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री अरविन्द नेताम : (क) जी हां । खुरपका तथा मुखपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकों के मूल्य के 50 प्रतिशत का योगदान लाभानुभोगियों को करना होता है ।

(ख) जी, नहीं । दो टीके लगाने की अपेक्षित लागत 8 रुपये वार्षिक है अतः लाभानुभोगियों को केवल 4 रुपए प्रतिवर्ष ही देने होते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : सभापति जी, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं कि इस देश में 20 करोड़ बैल वंशी पशु हैं। कुल 26 करोड़ हैं जिनमें भैंस भी शामिल हैं। इस बैल वंशी को ही यह रोग अधिक लगता है । मैंने अपने प्रश्न के द्वारा यह मांग की है कि 20 प्रतिशत मूल्य केन्द्र शासन अपनी तरफ से और वहन करे।

इसमें जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा दुखास्पद है । मेरे "ख" प्रश्न का जो उत्तर है वह यह है कि "जी" नहीं । दो टीके लगाने की अपेक्षित लागत 8 रुपए वार्षिक है" । यह टीके क्या साल भर लगते रहते हैं ? जब यह रोग होता है, फुट एण्ड माउथ डिसीज, तो 8, 10, 15 दिनों तक पशु खाना नहीं खा पाता, चल नहीं सकता । यह अधिकतर ऐसे पशुओं में जो गरीब वर्ग के पास ज्यादा होते हैं, पाया होता है जो इनका इलाज नहीं करा सकते । इसलिए हमने यह मांग की है कि गरीबों के लिए कम से कम इसकी छूट आप दें । इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, इस बीमारी के विषय में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसमें मैंने उत्तर दिया है कि इस बीमारी में हम भी मदद कर रहे हैं राज्य सरकारों की । सेंटर स्पान्सर्ड स्कीम के तहत राज्य सरकारों का भी इसमें योगदान होता है । क्योंकि यह मुख्यतया राज्य का मामला है और एक ही बीमारी में हम केन्द्रीय सरकार की तरफ से मदद करते हैं, जिसमें 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है और 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और बाकी जो है वह बेनिफिसरीज को वहन करना पड़ता है। सभापति महोदय, जो भी इस तरह का पशु पालन करते हैं उनको साल में दो टीके लगाने पड़ते हैं । इसमें एक टीके की कीमत 4 रुपये लगती है । साल में जो बेनिफिसरीज हैं उनको 4 रुपये वहन करना पडता है, यह वहन करना मैं समझता हूं कि वाजिब है । सेंटर स्पांसर्ड स्कीम में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसे करते हैं ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया ।

MR. CHAIRMAN : They can afford to pay Rs. 4.

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : मैं दूसरा सप्लीमेंटरी यह करना चाहता हूं कि साल भर में कितने पशुओं को फुट एंड माउथ के टीके लगाये जाते हैं, यह जानकारी मंत्री जी दें ?

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, 1991-92 में करीब 10 मिलियन: 1992-93 में करीब 12.5 मिलियन, 1993-94 में करीब 28 मिलियन टीके लगाये गये, इस फुट एंड माउथ के ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : यह आधे प्रश्न का उत्तर है । सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें केन्द्रीय शासन पर कितना वित्तीय भार पड़ता है ।

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा 25 प्रतिशत गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बियर करती है और 25 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट करती है । इस प्रकार से इसका प्लान अलोकेशन में एक साल में करीब 1180 लाख का प्रावधान है और इस प्रकार से हर पंचवर्षीय योजना में दे रहे हैं । हम जिस ढंग से राज्य सरकारें कहेंगी, हम मदद करने के लिये तैयार हैं ।

श्री जर्नादन यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो निरोधक टीका है इसके न लगने के कारण प्रतिवर्ष कितने पशुओं को मुखरी की बीमारी होती है और उससे मरते हैं। अगर निशुल्क सेवा करें तो गरीबों के पशु जो हर साल इस बीमारी से मर जाते हैं, उससे गरीबों को त्राण होगा ?

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, इस बीमारी के लिये जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है उससे इसमें कमी आयी है । मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि 1991 में 953 जगहों पर इस ढंग की बीमारी फैली थी और 1992 में 987 जगह और 1993 में 741 जगह । तो इस प्रकार से धीरे-धीरे इसका प्रभाव कम हुआ है। टीके की मात्रा क्योंकि बढ़ी है इसलिए बीमारी की रोकथाम हुई है ।

श्री जर्नादन यादव : पशुपालकों के पास पैसा नहीं है और टीका न लगने से पशुओं में यह बीमारी ज्यादा बढ़ रही है । यह खत की बीमारी है । अगर एक पशु को होती है तो सारे पशुओं को हो जाती है । इस दृष्टि से मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

श्री अरविन्द नेताम : हर साल बीमारी में राज्य सरकारें इसकी व्यवस्था करती हैं । इस बीमारी में राज्य सरकारों की केन्द्रीय सरकार मदद कर रही है ।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह भारत का बहुत जाना-पहचाना पुराना रोग है । यह कोई नयी बीमारी नहीं है । इस संबंध में जिस प्रकार मनुष्यों

की बीमारियों के उन्मूलन की राष्ट्रव्यापी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं जैसे चेचक के लिए योजना बनाई गई थी, क्या सरकार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाना चाहेगी ? जैसे ही पशुओं का बच्चा पैदा होता है उसको इस टीके से आरोपित करके इस बीमारी के राष्ट्र से पूर्ण उन्मूलन की कोई योजना सरकार कार्यान्वित करना चाहेगी, यदि हां तो उसकी कार्य योजना बनाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, जैसे कि मैंने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने इसका प्रावधान बढ़ाया है और सरकार का उद्देश्य यह है कि अधिकतम टीके लगाए जाएं ताकि इसकी व्यवस्था हो सके । इसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना में दो तीन बातें हैं जिसमें सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टीके लगाए जाएं और इसके इलावा भी कुछ सैंटर्ज हम लोगों ने स्थापित किए हैं और उनको मजबूत किया जा रहा है क्योंकि इसका इलाज यह है कि जितने अधिकतम टीके लगाए जाएंगे उतना ही अच्छा होगा ।

SHRI SOM PAL : Sir, this is a very non-commital reply. I am on launching a national eradication plan to earidcate the disease completely from the country.

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है ।

श्री सोमपाल : इसमें क्या कठिनाई है ? सारा मेकेनिज्म बना हुआ है तो आप क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने प्लान एलोकेशन बढ़ाया है और उसके टीके की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं । इसमें राज्य सरकारें जिस ढंग से सामने आएंगी हम निश्चित रूप से मदद करेंगे ।

*465. [*The Questioner (Chaudhary Harmohan Singh) was absent. For answer* Col.....infra.]

466. [*The Questioner (Shrimati Urmila ben Chimanbhai Patel) was absent. For answer vide* col.....infra.]

Out of course Maths paper for XII Standard

*467. SHRI VIRENDRA KATARIA :†
SHRI SOM PAL :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken with regard to the difficult, lengthy and out of course Mathematics paper for class XII students of the CBSE examination conducted in March, 1994;

(b) if so, the details thereof;

(c) if no decision has so far been taken, by when it is likely to be taken and the reasons for delay in arriving at a decision in the matter, which is causing concern to the tens of thousands of students and their parents; and

(d) what measures are contemplated to ensure that such things do not recur in future?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Soon after the Class XII Mathematics Examination held on 4-3-1994, the Central Board of Secondary Education (CBSE) had set up a Committee of Subject Experts of mathematics to examine the complaints and allegations with regard to the question papers under reference. The Committee consisted of 11 members and 3 co-opted members drawn from NCERT, University of Delhi, Principals and senior teachers of mathematics of Government and Independent schools and represented a cross section of experts and practitioners of mathetion of experts and practioners of mathematics teaching. The Expert Committee submitted a unanimous report on 15-3-94 which indicated, briefly, that though the question papers under reference could not be termed as being of higher difficulty level, they contained some questions involving lengthy calculations resulting in possible loss of time to a large number of examinees. The

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Kataria.